

ईधन बचाने ट्रेवलर में निकले जनप्रतिनिधि और अधिकारी, सिंहस्थ तैयारी का बदलता स्वरूप देखा

काह डायवर्सन से घाटों तक विकास कार्यों का निरीक्षण
टनल में उतरे तो दिखा अद्भुत नजारा

के लिए व्यवस्थित, आधुनिक और सुविधायुक्त बनाया जा रहा है. उनका कहना था कि सामान्यतः दो वर्षों में पूरे होने वाले कार्य एक वर्ष में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यदि यही गति बनी रही तो समय से पहले कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी.

सांसद बोले- ऐतिहासिक

सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि काह डायवर्सन परियोजना को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर की सुरंग परियोजना का कार्य चल रहा हो. उन्होंने कहा कि शिप्रा को स्वच्छ बनाने की दिशा में यह ऐतिहासिक पहल है.

धरातल पर काम

राज्यसभा सांसद उमेशनाथ महाराज ने कहा कि वर्षों से शिप्रा शुद्धिकरण की बात होती रही, लेकिन अब पहली बार बड़े स्तर पर धरातल पर काम दिखाई दे रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालु स्वच्छ शिप्रा में स्नान कर सकेंगे.



विधायक बोले- बेहतर कार्य

विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सराहना करते हुए कहा कि कई स्थानों पर निर्माण सामग्री की जांच कराई गई और कार्य उच्च मापदंडों के अनुसार होते दिखाई दिए.

महापौर बोले- व्यापक कार्य

महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सड़क, घाट, पुल और जल प्रबंधन जैसे सभी क्षेत्रों में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं.

उज्जैन की नई पहचान बनेंगे

नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कहा कि शिप्रा के दोनों किनारों पर विकसित हो रहे घाट आने वाले समय में उज्जैन की नई पहचान बनेंगे और सिंहस्थ को दिव्य स्वरूप देंगे.

अद्भुत उदाहरण

उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी ने कहा कि काह डायवर्सन परियोजना इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में उज्जैन का

स्वरूप तेजी से बदल रहा है.

ये रहे मौजूद

निरीक्षण यात्रा में सम्भागायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद संत उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव और उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे. सभी ने मिनी बस के माध्यम से निर्माण स्थलों का भ्रमण किया.

29 किलोमीटर तक बन रहे नए घाट

शिप्रा नदी के किनारे बन रहे नए घाटों का भी विस्तार से निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 29 किलोमीटर क्षेत्र में नए घाट विकसित किए जा रहे हैं, जबकि पहले से बने घाटों को भी जोड़ा जाएगा. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सिंहस्थ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. विस्तृत घाट निर्माण से स्नान व्यवस्था

24.5 मीटर नीचे उतरकर

देखा काह डायवर्सन का काम

निरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव काह डायवर्सन परियोजना रही. जनप्रतिनिधियों ने लगभग 24.5 मीटर गहराई तक उतरकर निर्माणधीन टनल का निरीक्षण किया. इंजीनियरों ने बताया कि यह परियोजना शिप्रा नदी को प्रदूषित जल से मुक्त करने की दिशा में सबसे बड़ी पहल है. लगभग 30 किलोमीटर लंबी इस योजना में वलोज डक्ट और भूमिगत टनल का निर्माण किया जा रहा है. टनल के भीतर पहुंच कर सफाई के लिए विशेष शाफ्ट भी बनाए जा रहे हैं.

अधिक सुव्यवस्थित होगी और श्रद्धालुओं को भीड़ के दबाव से राहत मिलेगी। घाटों तक पहुंच मार्ग, सीढ़ियां और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है.

नए पुलों से आसान होगा आवागमन

भूखी माता क्षेत्र में निर्माणधीन पुल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने बताया कि लगभग 175 मीटर लंबे पुल का निर्माण तेज गति से चल रहा है. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यातायात और भीड़ प्रबंधन होती है, ऐसे में नए पुल और सड़कें आवागमन को सुगम बनाएंगी.

सामग्री की जांच

निरीक्षण दल ने निर्माण सामग्री की परीक्षण प्रयोगशाला का भी अवलोकन किया. यहां सीमेंट, सरिया, गिट्टी सहित अन्य निर्माण सामग्री की नियमित जांच की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक परीक्षण का रिपोर्ट सुनिश्चित रखा जा रहा है ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी बनी रहे. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन के लिए बनने वाले स्थायी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रहा है.

मेडिकल कॉलेज पर भी फोकस

निरीक्षण दल ने शहर में विकसित हो रही मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं का भी जायजा लिया. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सिंहस्थ के साथ-साथ भविष्य के उज्जैन को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. उनका कहना था कि इन परियोजनाओं से शहर को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा.

सीएम परिवहन सेवा : पहले चरण में 5206 बसें चलेंगी

पहले चरण के लिए 1164 मार्गों का चयन
दो चरणों में शुरू होगी सेवा
शीघ्र सेवा शुरू करने के सीएम के निर्देश



प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 मई. प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के पहले चरण में कुल 1,164 मार्गों पर लगभग 5,206 बसों का संचालन आगले दो सालों में किया जाएगा. इन सभी बसों की सुचारू मॉनिटरिंग के लिए एक दक्ष एवं इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है.

योजना के पहले चरण में इंदौर क्षेत्र के कुल 121 मार्गों में कुल 608 बसें, उज्जैन क्षेत्र के

120 मार्गों में 371 बसें, भोपाल क्षेत्र के 104 मार्गों में 398 बसें, जबलपुर क्षेत्र के 83 मार्गों पर 309 बसें, सागर क्षेत्र के 92 मार्गों में 344 बसें, ग्वालियर क्षेत्र के 65 मार्गों में 298 बसें तथा रीवा क्षेत्र के 35 मार्गों में 184 बसें चलाई जाएंगी. योजना के तहत चलाई जाने वाली सभी बसों का रंग एक जैसा होगा, ताकि एकरूपता बनी रहे.

यह जानकारी गुरुवार को

मंत्रालय में प्रजेंटेशन के दौरान सचिव परिवहन विभाग मनीष सिंह ने दी. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शीघ्र ही ये सेवा शुरू करने के निर्देश दिए. इस पर सचिव परिवहन विभाग ने बताया कि योजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से प्रक्रियागत काम जारी है. यह योजना दो चरणों में चलाई जाएगी. इसके लिए प्रदेश में 7 क्षेत्र क्रमशः इंदौर, उज्जैन,

भोपाल नर्मदापुरम सहित, जबलपुर, सागर, ग्वालियर चंबल सहित एवं रीवा शहडोल सहित स्थापित किए गए हैं. पहले चरण में चलाई जाने वाली बसों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों से उपनगरीय क्षेत्रों तक विस्तारित मार्ग मंजूरी की विभागीय अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अन्य क्षेत्रों के विस्तारित मार्गों की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी.

मध्य राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय का होगा गठन

बैठक में बताया गया कि हाल ही में मध्य में हुई सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की बैठक के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा इन दोनों योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की पहल की बेहद सराहना की गई है. इसी कमेटी की अनुशंसा पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अलग से मध्य राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन भी किया जा रहा है. सचिव परिवहन ने बताया कि प्रदेश में ई-डिटेक्शन प्रणाली प्रारंभ करने की व्यवस्था की जा रही है. इस पर काम प्रगति पर है. इस प्रणाली से विहित स्थानों पर लगे कैमरों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट अपने आप स्कैन हो जाएगी. स्कैन किए गए वाहन क्रमांक से दस्तावेज वाहन पोर्टल से स्वतः जांच होकर सीधे ऑनलाइन भेज दिया जाएगा.

परिवहन चौकियों को इंटीग्रेटेड करें

सीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और अधिक आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाए. इसके लिए परिवहन चौकियों को शीघ्र ही इंटीग्रेटेड करने के प्रयास किए जाएं. प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग करा ली जाए, जिससे जरूरतमंदों को जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेस मुहैया कराई जा सकें. विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही एम्बुलेंस सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिससे दुर्घटना क्षेत्रों में जरूरतमंद तक 30 मिनट से भी कम समय में एम्बुलेंस आती मोड में पहुंच जाए.

पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 21 मई. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सूबेदार एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं. 500 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल तक भोपाल, जबलपुर, सागर और सीधी सहित चार शहरों में आयोजित की गई थी. परीक्षा परिणाम 18 मई को मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए गए थे.

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की

प्रक्रिया 5 जून से 11 जून 2026 तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड, जहांगीराबाद तथा जबलपुर के 6वीं वाहिनी, एसएएफ, रांडी स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित होगी. मंडल ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे आधिकारिक पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर निर्धारित तिथि एवं केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र या तिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रक्रिया के दौरान आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा.

हनी ट्रैप सिंडिकेट में एक-एक कर पकड़ में आ रही कड़ियां

सामने रहा है ब्लैकमेलिंग का बड़ा जाल, सागर से पकड़ी नेटवर्क ऑपरेटर महिला

नव भारत न्यूज इंदौर. पिछले दिनों शहर में सामने आए हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. सागर से एक और महिला को गिरफ्तारी के साथ अब तक इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से नेताओं, कारोबारियों और अफसरों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग का बड़ा नेटवर्क चला रहा था.



शर्मा, जितेंद्र पुरोहित को हिरासत में ले चुकी है. इस तरह अब तक 7 से अधिक आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं. वहीं पूछताछ में सामने आया है कि श्वेता विजय जैन के जरिए रेणु और

अलका के बीच संपर्क हुआ था, जिसके बाद तीनों ने मिलकर पूरा गिरोह खड़ा किया था. रेणु ने अलका को कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क होने की जानकारी दी थी, जिनमें नेता, प्रॉपर्टी कारोबारी, फाइनेंस और अफसर शामिल थे. इन्हें निशाना बनाकर आसानी से मोटी रकम वसूलने की योजना बनाई गई, जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह ने निमाडू क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता को भी टारगेट किया था. वहीं, एक कारोबारी को ब्लैकमेल करते समय आरोपियों ने बड़े लोगों के आपत्तिजनक वीडियो होने का हवाला देकर दबाव बनाया.

अन्य की तलाश जारी : डीसीपी

पूरे मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और जांच में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं. आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

मोबाइल में मिली ऑडियो-वीडियो फाइलें

पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से कुछ ऑडियो वीडियो फाइलें भी मिली हैं, जिन्हें अहम सबूत माना जा रहा है. इन डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और पीड़ितों की पहचान की जा रही है. क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि श्वेता विजय जैन और अलका दीक्षित की दोस्ती जेल में हुई थी. बाद में रेणु को इस नेटवर्क में जोड़ा और तीनों ने मिलकर पूरे ब्लैकमेलिंग रैकेट की रूप रेखा तैयार की. चिट्ठे ठाकुर से जुड़े इस मामले में यह भी सामने आया है कि शिकायत के करीब 19 दिन बाद एफआईआर दर्ज की. चिट्ठे ठाकुर पहले से ही आजाद नगर थाने में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी थे.

मोबाइल में मिली ऑडियो-वीडियो फाइलें भी मिली हैं, जिन्हें अहम सबूत माना जा रहा है. इन डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और पीड़ितों की पहचान की जा रही है. क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि श्वेता विजय जैन और अलका दीक्षित की दोस्ती जेल में हुई थी. बाद में रेणु को इस नेटवर्क में जोड़ा और तीनों ने मिलकर पूरे ब्लैकमेलिंग रैकेट की रूप रेखा तैयार की. चिट्ठे ठाकुर से जुड़े इस मामले में यह भी सामने आया है कि शिकायत के करीब 19 दिन बाद एफआईआर दर्ज की. चिट्ठे ठाकुर पहले से ही आजाद नगर थाने में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी थे.

मुद्दा : तीन लाख से अधिक किसानों के नाम योजना से चुपचाप हटाने का आरोप लगाया पूर्व सीएम ने

भाजपा राज में किसानों के साथ छलावा हो रहा है : कमलनाथ

विशेष संवाददाता भोपाल, 21 मई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर किसानों के साथ 'हर स्तर पर धोखा' करने का आरोप लगाया. उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को सख्खा में आई कमी और शिवपुरी जिले में गेहूं खरीदी भूगतान में कथित साइबर धोखाधड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा. कमलनाथ ने एक बयान में कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश

में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से तीन लाख से अधिक किसानों के नाम चुपचाप हटा दिए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक ओर योजना का व्यापक प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 86.49 लाख किसानों को लाभ मिला था, लेकिन वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर करीब 83.01 लाख



रह गई. उन्होंने कहा कि तीन लाख से अधिक किसानों को बिना पारदर्शिता के योजना से बाहर कर दिया गया है.

कमलनाथ ने यह भी कहा कि 80 हजार से अधिक किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तक लंबित है, जबकि करीब 1.87 लाख किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण पात्र किसानों को किस्त का भुगतान नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की कि पात्र किसानों को लंबित राशि तत्काल जारी की जाए और अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं के माध्यम से किसानों को परेशान करना बंद किया जाए.

शिवपुरी जिले में गेहूं खरीदी भुगतान में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं का भुगतान किसानों के खातों में पहुंचने के बजाय संदिग्ध बैंक खातों में पहुंचने की खबरें बेहद गंभीर हैं. उन्होंने इसे साइबर धोखाधड़ी का मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पूरे प्रकरण को उच्चस्तरीय जांच तथा प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की.

प्रदेश में 1.49 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त

विशेष संवाददाता भोपाल, 21 मई. मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशभर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई कर 1.49 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अवैध नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की है. जब्त सामग्री में गांजा, स्मैक, एमडी ड्रग्स, डोडा चूरा, नशीली कफ सिरप और इंजेक्शन शामिल हैं. इंदौर में पुलिस ने पांच अंतरराज्यीय तस्करो को गिरफ्तार कर एमडी ड्रग्स, अवैध हथियार



और करीब एक करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की. वहीं सीधी जिले में 'ऑपरेशन प्रहार 2.0' के तहत पुलिस ने नशीली कफ सिरप तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 900 से अधिक ऑनरेक्स सिरप की बोतलें और वाहन जब्त किए. मऊगंज, अनूपपुर, शिवपुरी,

श्योपुर और गुना जिलों में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांजा और स्मैक बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा भोपाल जोआरपी और जबलपुर क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग कार्रवाई में गांजा, नशीले इंजेक्शन और नकदी बरामद की.